



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 03 सितम्बर, 2025 ई०

भाद्रपद 12, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 328/XXXVI (3)/2025/41(1)/2025

देहरादून, 03 सितम्बर, 2025

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन मा० राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित ‘उत्तराखण्ड विनियोग (2025-26 का अनुपूरक) विधेयक, 2025’ पर दिनांक 02 सितम्बर, 2025 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या: 14 वर्ष, 2025 के रूप में सर्व-साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड विनियोग (2025-26 का अनुपूरक) अधिनियम, 2025

(अधिनियम संख्या 14, वर्ष 2025)

31 मार्च, 2026 ई0 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय के लिये राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये,

अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

- | | |
|---|---|
| संक्षिप्त नाम | 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विनियोग (2025-2026 का अनुपूरक) अधिनियम, 2025 है। |
| उत्तराखण्ड की संचित निधि में से वर्ष 2025-26 के लिये रु0 53153897000 का निकाला जाना | 2. ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये, जो 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेंगे, उत्तराखण्ड की संचित निधि में से उतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिन का कुल योग रु0 53153897000 (रुपया पाँच हजार तीन सौ पन्द्रह करोड़ अड़तीस लाख सत्तानवें हजार मात्र) होता है, अधिक न हो। |
| विनियोग | 3. इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की संचित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग, 31 मार्च, 2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष 2025-26 के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, जो अनुसूची में दिये हुये हैं। |

अनुसूची
अनुपूर्वक आय व्ययक 2025-26
(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनुधिक (धनराशि हजार रुपये में)			
		क्षेत्री	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संविदा विधि पर प्रतिष्ठ	योग
1	2	3			
01	विधान सभा	राजस्व :	320000	2000	322000
02	राज्यपाल	राजस्व :	0	400	400
04	न्याय प्रशासन	राजस्व :	55649	73930	129579
		गृहणी :	1000	0	1000
05	निर्यात	राजस्व :	224545	0	224545
06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व :	445701	0	445701
		गृहणी :	3576598	0	3576598
07	बिरा, कर, नियोजन, परिवारालय तथा अन्य सेवायें	राजस्व :	819527	2353600	3173127
		गृहणी :	2591801	0	2591801
08	आवकरी	राजस्व :	71640	0	71640
09	लोक सेवा आयोग	राजस्व :	750	0	750
10	मुख्य एवं जेव	राजस्व :	275031	0	275031
		गृहणी :	760000	0	760000
11	शिक्षा, लेन एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व :	5198021	0	5198021
		गृहणी :	540300	0	540300
12	विक्रितता एवं परिवार कल्याण	राजस्व :	1502424	0	1502424
		गृहणी :	1834781	0	1834781
13	जलसुविधि, आवास एवं मनोरंजन विकास	राजस्व :	1452500	0	1452500
		गृहणी :	6730998	0	6730998
14	सुरक्षा	राजस्व :	1226988	0	1226988
15	कल्याण योजनायें	राजस्व :	393146	0	393146
		गृहणी :	983705	0	983705
16	धन और दोलन	राजस्व :	300234	0	300234
17	कृषि कार्य एवं अनुसंधान	राजस्व :	1119036	0	1119036
		गृहणी :	100001	0	100001
18	सहकारिता	राजस्व :	1704	0	1704
		गृहणी :	23000	0	23000
19	ग्राम्य विकास	राजस्व :	599082	0	599082
		गृहणी :	400001	0	400001
20	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व :	279200	0	279200
		गृहणी :	150001	0	150001
21	ऊर्जा	राजस्व :	1406300	0	1406300
		गृहणी :	200000	0	200000
22	लोक निर्माण कार्य	राजस्व :	800002	100000	900002
		गृहणी :	11010000	0	11010000
23	उद्योग	राजस्व :	110900	0	110900
24	परिवहन	राजस्व :	136200	0	136200
		गृहणी :	1885503	0	1885503
25	धरातल	राजस्व :	445827	0	445827
26	पर्यटन	राजस्व :	81950	0	81950

अनुसूची
अनुपूर्वक आय व्ययक 2025-26
(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदान	रोवाये और प्रयोजन	निरूपित मनराशियों से अनुसूचित (अनुसूचित द्वारा रुपये में)			
		श्रेणी	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संश्लिष्ट निधि पर भारित	योग
1	2	3			
		मूली :	250000	0	250000
27	वन	राजस्व :	507501	0	507501
		मूली :	20000	0	20000
28	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व :	100849	0	100849
		मूली :	50000	0	50000
29	औद्योगिक विकास	राजस्व :	77693	1151	78844
		मूली :	1	0	1
30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व :	800332	0	800332
		मूली :	436227	0	436227
31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व :	237874	1	237875
		मूली :	86292	0	86292
	योग	राजस्व :	18992606	2531082	21523688
	योग	मूली :	31630209	0	31630209
	महा योग		50622815	2531082	53153897

आज्ञा से,
धनंजय चतुर्वेदी,
प्रमुख सचिव।

उद्देश्य और कारण

भारत का संविधान के अनुच्छेद 204 सपठित अनुच्छेद 205 के अधीन विधान सभा द्वारा अनुपूरक अनुदानों की मांगें स्वीकृत किये जाने के बाद राज्य विधान सभा में एक विनियोग विधेयक प्रस्तुत करना आवश्यक है।

प्रस्तावित विधेयक यह उपबन्धित करता है कि वित्तीय वर्ष 2025-2026 के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा स्वीकृत अनुपूरक अनुदान मांगों तथा राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्ययों के लिये जो धन अपेक्षित है, उसका विनियोग उत्तराखण्ड की संचित निधि में से किया जा सके।

पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री

No. 328/XXXVI(3)/2025/41(1)/2025

Dated Dehradun, September 03, 2025NOTIFICATIONMiscellaneous

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Appropriation (Supplementary 2025-26) Act, 2025' (Act No. 14 of 2025).

As passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 02 September, 2025.

THE UTTARAKHAND APPROPRIATION (SUPPLEMENTARY 2025-26) ACT,
2025

(Act No. 14 of 2025)

An

Act

to provide for the authorization of payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State to the services for the financial years 2025-26 ending on the 31st day of March 2026.

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislature in the Seventy-Sixth Year of the Republic of India as follows-

- | | |
|--|---|
| Short title | 1. This Act may be called the Uttarakhand Appropriation (Supplementary 2025-2026) Act, 2025. |
| Issue of Rs. 53153897000 out of the Consolidated Fund of Uttarakhand to meet certain excess expenditure for the year 2025-2026 | 2. From and out of the Consolidated Fund of Uttarakhand, there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column-3 of the Schedule, amounting in the aggregate to the sums of Rs. 53153897000 (Rs. Five Thousand Three Hundred Fifteen Crore Thirty-Eight Lakh Ninety Seven Thousand Only) towards defraying the several charges, which shall come in course of payment during the financial year 2025-26 ending on the 31 st day of March, 2026 in respect of the services and purposes specified in column - 2 of the Schedule. |
| Appropriation | 3. The sums, authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of Uttarakhand by this Act, shall be appropriated for the services and purposes, expressed in the Schedule in relation to the financial year 2025-26 ending on the 31 st day of March, 2026. |

THE SCHEDULE
Supplymentary Budget 2025-26
(See Section 2 and 3)

Grant	Services and Purpose	Sums not exceeding the following (In thousand)			
		Category	Voted by the Legislative Assembly	Charged upon Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3			
01	Legislative Assembly	Revenue:	320000	2000	322000
02	Governor	Revenue:	0	400	400
04	Judicial Administration	Revenue:	55649	73930	129579
		Capital:	1000	0	1000
05	Election	Revenue:	224545	0	224545
06	Revenue and General Administration	Revenue:	445701	0	445701
		Capital:	3576598	0	3576598
07	Finance, Taxes, Planning, Secretariat and Miscellaneous Service	Revenue:	819527	2353600	3173127
		Capital:	2591801	0	2591801
08	Excise	Revenue:	71640	0	71640
09	Public Service Commission	Revenue:	750	0	750
10	Police and Jail	Revenue:	275031	0	275031
		Capital:	760000	0	760000
11	Education, Sports, Youth Welfare and Culture	Revenue:	5198021	0	5198021
		Capital:	540300	0	540300
12	Medical and Family Welfare	Revenue:	1502424	0	1502424
		Capital:	1834781	0	1834781
13	Water Supply, Housing and Urban Development	Revenue:	1452500	0	1452500
		Capital:	6730998	0	6730998
14	Information	Revenue:	1226988	0	1226988
15	Welfare Schemes	Revenue:	393146	0	393146
		Capital:	983705	0	983705
16	Labour and Employment	Revenue:	300234	0	300234
17	Agriculture and Research	Revenue:	1119036	0	1119036
		Capital:	100001	0	100001
18	Co-operative	Revenue:	1704	0	1704
		Capital:	23000	0	23000
19	Rural Development	Revenue:	599082	0	599082
		Capital:	400001	0	400001
20	Irrigation and Flood	Revenue:	279200	0	279200
		Capital:	150001	0	150001
21	Energy	Revenue:	1406300	0	1406300
		Capital:	200000	0	200000
22	Public Works	Revenue:	800002	100000	900002
		Capital:	11010000	0	11010000
23	Industries	Revenue:	110900	0	110900
24	Transport	Revenue:	138200	0	138200
		Capital:	1885503	0	1885503
25	Food	Revenue:	445827	0	445827
26	Tourism	Revenue:	81950	0	81950

THE SCHEDULE
Supplymentary Budget 2025-26
(See Section 2 and 3)

Grant	Services and Purpose	Sums not exceeding the following (In thousand)			
		Category	Voted by the Legislative Assembly	Charged upon Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3			
		Capital:	250000	0	250000
27	Forest	Revenue:	507501	0	507501
		Capital:	20000	0	20000
28	Animal Husbandry	Revenue:	100849	0	100849
		Capital:	50000	0	50000
29	Horticulture Development	Revenue:	77693	1151	78844
		Capital:	1	0	1
30	Welfare of Scheduled Castes	Revenue:	800332	0	800332
		Capital:	436227	0	436227
31	Welfare of Scheduled Tribes	Revenue:	237874	1	237875
		Capital:	86292	0	86292
	TOTAL	Revenue:	10992606	2531082	21523688
	TOTAL	Capital:	31630209	0	31630209
	GRAND TOTAL		50622815	2531082	53153897

By Order,

DHANANJAY CHATURVEDI,

Principal Secretary.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Article 204 of the Constitution of India read with article 205 requires that an Appropriation Bill should be introduced in the State Legislative Assembly after the demands for Supplementary Grants have been voted by the Legislative Assembly.

The proposed Bill makes provision for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of Uttarakhand of all moneys required to meet the Supplementary Grants made as approved by the Uttarakhand Legislative Assembly and expenditure charged upon the Consolidated Fund of the State in respect of Financial Year 2025-2026.

Pushkar Singh Dhama
Chief Minister